दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 09.02.2024

रि.या.(सि) 12061/2019 और सि.वि.आ. 49379/2019 -ओ-1, आर-10

निगार फातिमा .....याचिकाकर्ता

द्वारा: सुश्री तान्या अग्रवाल, अधिवक्ता (वीसी)

बनाम

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और अन्य

..... प्रत्यार्थिगण

द्वारा: श्री आर.वी.सिन्हा और श्री अमित सिन्हा, अधिवक्तागण।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री रेखा पल्ली

माननीय न्यायमूर्ति श्री रजनीश भटनागर

<u>रेखा पल्ली, न्या (मौखिक)</u>

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत वर्तमान रिट याचिका मूल आवेदन (मू.आ.) संख्या 3844/2018 में विद्वान केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (विद्वान न्यायाधिकरण) द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2019 को चुनौती देने की मांग करती है। आक्षेपित आदेश के माध्यम से, विद्वान न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता के मूल आवेदन को खारिज कर दिया है जिसमें उसने मांग की थी कि उसका बेटा मुजीबुद्दीन सिद्दीकी, जिसे

मई, 2017 में ग्रुप डी कर्मचारी के रूप में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया था, को ग्रुप सी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाए।

2. याचिका के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने पति की मृत्यु के बाद 2012 में ग्रुप डी कर्मचारी के रूप में अनुकंपा के आधार पर अपने बेटे की नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। हालाँकि, अनुकंपा नियुक्तियों से निपटने वाली समिति द्वारा उनके मामले पर विचार किए जाने से पहले, उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली और इसलिए, याचिकाकर्ता ने 15.07.2016 को प्रत्यर्थी के सहायक महाप्रबंधक को एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें अनुरोध किया गया कि अब उस पर ग्रुप सी पद के लिए विचार किया जाए। हालाँकि, इस तथ्य को समिति के संज्ञान में नहीं लाया गया और परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता के बेटे को ग्रुप सी कर्मचारी के रूप में नियुक्त करने के बजाय 2017 में ग्रुप डी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया। जिसके लिए जब समिति ने नियुक्ति के लिए उनके नाम की सिफारिश की तो उनके पास अपेक्षित योग्यता थी। उनका तर्क है कि याचिकाकर्ता के साथ भेदभाव किया गया है, क्योंकि आवेदन के लंबित रहने के दौरान अर्जित योग्यता के आधार पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के बेटे का मामला खारिज कर दिया गया है, समान राहत चाहने वाले अन्य उम्मीदवारों के समान आवेदन स्वीकार कर लिए गए थे। इसलिए, वह प्रार्थना करती है कि रिट याचिका को अनुमति दी जाए और प्रतिवादियों को उसके बेटे को उसकी

नियुक्ति की तारीख से सभी परिणामी लाभों के साथ ग्रुप सी कर्मचारी के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया जाए।

3. दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता के बेटे ने बिना किसी आपत्ति के ग्रुप डी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, वर्तमान याचिका केवल इस आधार पर खारिज की जा सकती है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता का बेटा बालिग है और इसलिए, याचिकाकर्ता के पास अपना मामला पेश करने का भी कोई अधिकार नहीं है। वह अंततः प्रस्तुत करता है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनुकंपा नियुक्ति उदारता नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य केवल मृत कर्मचारी के परिवार को उसकी मृत्यु के कारण अचानक आए संकट से निपटने में मदद करना है, उत्तरदाताओं को यह निर्देश देना उचित है कि केवल योग्यता जमा करने की तिथि पर ही नियुक्ति की जाए। अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन पर विचार किया जाएगा। इसलिए, वह प्रार्थना करते है कि रिट याचिका खारिज कर दी जाए।

4. जवाब में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के बेटे की ओर से एक आवेदन दायर किया गया है जिसमें सह-याचिकाकर्ता के रूप में उसकी अभियोग की मांग की गई है। इसलिए, उनका तर्क है कि वर्तमान याचिका को याचिकाकर्ता के बेटे की ओर से याचिका के रूप में माना जा सकता है।

5. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर विचार करने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, हमारा विचार है कि अब याचिकाकर्ता के बेटे द्वारा वर्तमान याचिका में मुकदमा चलाने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है, इस बात की जांच करने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा कि क्या याचिकाकर्ता के पास मू.आ. दाखिल करने का कोई अधिकार था, इसलिए हम योग्यता के आधार पर याचिका से निपटने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

6. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, याचिकाकर्ता की एकमात्र शिकायत यह है कि भले ही याचिकाकर्ता के बेटे ने स्नातक की डिग्री हासिल कर ली है, इसका प्रमाण पत्र प्रत्यर्थियों की जानकारी में जुलाई, 2016 में लाया गया था। समिति ने इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा और परिणामस्वरूप सिफारिश की कि अपना आवेदन जमा करने के समय उसके द्वारा गृहीत योग्यता के आधार पर, उन्हें ग्रुप सी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाए। इस पहलू पर पक्षों की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों की सराहना करने के लिए, पैरा 5 में निहित आक्षेपित निर्णय के प्रासंगिक उद्धरण पर ध्यान देना उचित होगा, जो निम्नानुसार है:

> *"5. दोनों पक्षों को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, स्पष्ट रूप से आवेदक के पास केवल हाई स्कूल कि डिग्री थी जैसा कि उसके द्वारा दायर अनुलग्नक आर -3 से दिखाया गया है। जब उन्होंने 23.01.2012 को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। इस प्रकार , सक्षम प्राधिकारी ने बीएसएनएल कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा दिनांक 21.12.2016 को जारी स्पष्टीकरण के*

*अनुसार समूह 'डी' पद के लिए आवेदक के मामले को सही तरीके से मंजूरी दे दी है, जो स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है कि सर्कल हाई पावर कमेटी द्वारा शैक्षिक योग्यता में किसी भी बाद के बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा। जबकि प्रत्यर्थी अपने अभिलेख से यह दिखाने में सक्षम हैं कि राहुल श्रीवास्तव और जितेंद्र कुमार नामक व्यक्तियों के पास क्रमशः बी.टेक (ईसी) और बी.कोम (द्वितीय वर्ष) की योग्यता थी और समूह 'ग के पद के लिए उनके मामले को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सही ढंग से अनुमोदित किया गया था जब उन्हें अनुकंपा आधार नियुक्तियों के लिए उनके आवेदन प्राप्त हुए थे। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की अर्हताओं का मूल्यांकन करना भी अधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों की योग्यता का मूल्यांकन करना और तदनुसार उनकी अर्हताओं के आधार पर पदों पर उन्हें नियुक्त करना प्रत्यर्थियों का विशेषाधिकार है। **नानक चंद बनाम दिल्ली जल बोर्ड,** 2007 (140) डीएलटी 489, के मामले में माननीय उच्च*

न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निम्नानुसार कहा : -

> *"14. सर्वोच्च न्यायालय का आदेश पूर्वोक्त निर्णयों से बहुत स्पष्ट है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदक की पात्रता पर विचार करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय का कार्य नहीं है और वह केवल यह कर सकते है कि यह देख सकते है कि सक्षम प्राधिकारी का निर्णय गलत*

तो नहीं है। उपरोक्त पृष्ठभूमि में हाथ में आए मामलों की जांच करने के बाद, यह न्यायालय तथ्यों के निष्कर्ष और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।

7. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि जब याचिकाकर्ता द्वारा अपने बेटे की अनुकंपा नियुक्ति के लिए 23.01.2012 को आवेदन किया गया था, तो वह स्नातक नहीं था और इसलिए, केवल ग्रुप डी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र था। यह प्रत्यर्थी का मामला है कि उम्मीदवार की पात्रता पर विचार करने के लिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करने की तिथि पर उम्मीदवार द्वारा रखी गई योग्यताओं को ही ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि यह अनुकंपा नियुक्ति की योजना का एक अभिन्न अंग है।

8. जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगातार माना गया है, अनुकंपा नियुक्ति खुले विज्ञापन द्वारा नियुक्ति के लिए सामान्य नियम का अपवाद है और इसलिए इसका सहारा केवल तभी लिया जा सकता है जब उम्मीदवार और उसका परिवार गरीबी में हों। परिणामस्वरूप, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की पात्रता नियोक्ता द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए बनाई गई नीति के आधार पर बनाई जाती है। इसलिए अनुकंपा नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की पात्रता को नीति के संदर्भ में सख्ती से माना जाना चाहिए। इस नीति की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जो सामान्य नियम का अपवाद है,

न्यायालय नीति में निर्धारित शर्तों के बारे में अपने स्वयं के विचारों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। इस संबंध में, ***इंडिया बैंक और अन्य बनाम प्रोमिला और अन्य (2020) 2 एससीसी 729*** मामले में अपने निर्णय के पैरा 20 में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों का संदर्भ दिया जा सकता है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

> ***"20.*** *हमें अनुकंपा रोजगार के मामलों पर लागू बुनियादी सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा यानी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के चरण में सहायता प्रदान की जा रही है, साथ ही अनुकंपा रोजगार सार्वजनिक रोजगार का वैकल्पिक तरीका नहीं है। यदि इन कारकों को ध्यान में रखा जाता है, तो यह देखा जाएगा कि प्रत्यर्थियों के पास समय के प्रासंगिक चरण में, मानदंडों के अनुसार, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए साधन थे, जिसका वे सामना कर रहे थे। इस प्रकार, किसी भी योजना के तहत देखा गया, प्रत्यर्थी लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं, हालांकि, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, यह केवल कर्मचारी के निधन की तारीख पर प्रचलित प्रासंगिक योजना है, जिसे केनरा बैंक [केनरा बैंक बनाम एम महेश कुमार, (2015) 7 एससीसी 412 में इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर लागू माना जा सकता था: (2015) 2 एससीसी (एल एंड एस) 539] .* ***न्यायिक समीक्षा में किसी योजना को प्रतिस्थापित करना या उसकी शर्तों में जोड़ना या घटाना अदालतों का काम नहीं है, जैसा कि हाल ही में इस न्यायालय द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम प्रकाश चंद [हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम प्रकाश चंद, (2019) 4 एससीसी 285: (2019) 1 एससीसी (एल एंड एस) 621] में जोर दिया गया है। (महत्व सन्निविष्ट)***

9. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अनुकंपा नियुक्ति केवल दुःखी परिवार के लिए एक सहायता के रूप में कार्य करने के लिए होती है जब उसके कमाने वाले सदस्य की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है और, इसलिए, जब संकट पहले ही खत्म हो चुका हो, तो समय बीतने के बाद दावा या पेशकश नहीं की जा सकती। अनुकंपा नियुक्ति कभी भी एक निहित अधिकार नहीं हो सकती है और मुख्य रूप से योजना की शर्तों के अनुसार सख्ती से दी जाने वाली एक विवेकाधीन राहत है। अनुकंपा नियुक्ति के मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, आवेदन जमा करते समय केवल योग्यता पर विचार करने की प्रत्यर्थियों की कार्रवाई, न कि उन योग्यताओं पर, जो परिवार के सदस्य बाद में हासिल कर सकते हैं, किसी भी तरह से मनमाना नहीं कहा जा सकता है। याचिकाकर्ता की इस दलील को स्वीकार करने से कि उसके बेटे द्वारा बाद में हासिल की गई योग्यताओं को समिति द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए था, ऐसे में एक स्थिति पैदा होगी जहां नियोक्ता को मृत कर्मचारी के बच्चों के बड़े होने के लिए वर्षों तक इंतजार करना होगा और फिर अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपेक्षित योग्यता हासिल करनी होगी। यह निश्चित रूप से अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य नहीं हो सकता।

10. हमने याचिकाकर्ता की इस दलील पर भी विचार किया है कि प्रत्यर्थियों ने याचिकाकर्ता के बेटे के साथ भेदभाव किया है लेकिन इस बेतुकी याचिका में कोई दम नहीं है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हमारे सामने प्रत्यर्थी

का विशिष्ट मामला है कि किसी भी मामले में, आवेदन की तारीख के बाद किसी उम्मीदवार द्वारा अर्जित योग्यता को ध्यान में नहीं रखा गया है।

11. उपरोक्त कारणों से, हम विवादित आदेश में बिल्कुल भी कोई खामी नहीं पाते हैं। तदनुसार, रिट याचिका विचारहीन होने के कारण सभी लंबित आवेदनों के साथ खारिज की जाती है।

(रेखा पल्ली)
न्यायाधीश

(रजनीश भटनागर)
न्यायाधीश

9 फरवरी 2024
एसीएम

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*